horizon hind खबर
www.horizonhind.com

हॉरइज़न हिन्द

RNI NO. : RAJBIL/2013/50688 पाक्षिक डाक पंजीयन.: RJ/AJ/161/2016-2018

वर्ष 7 | अंक 7 | हिन्दी/अंग्रेजी पाक्षिक | अजमेर, 10 जनवरी, गुरुवार 2019 | सम्पादकः नरेश राघानी | पृष्ठ-4 | मूल्य 5 रुपये

'चुनाव हारे हुए प्रत्याक्षियों को नियुक्तियाँ देने से नहीं होगा कांग्रेस को लाभ'

'समझदारी से राजनैतिक पदों पर मनोनयन है कांग्रेस हेतु लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र'

नरेश राघानी

अजमेर। राजस्थान में राजनैतिक बदलाव का दौर शुरू है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्री परिषद के गठन के बाद अब विभागों की घोषणा भी कर दी गयी है। प्रदेश के राजनैतिक तबके की अब नज़र है ए सरकार द्वारा की जाने वाली बोर्ड और प्राधिकरण आदि पर नियुक्तियों पर' । वैसे तो इस तरह के मनोनीत किये जाने वाले पदों पर हमेशा 'मुख्यमंत्री के करीबी' और शीर्ष नेतृत्व के टच में लगातार बने रहने वाले लोगों को ही मनोनीत किया जाता है। परंतु इस बार ज़रा परिस्थितियाँ अलग हैं। क्योंकि 'कुछ महीने बाद कांग्रेस को फिर लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में आना है' । इसलिए ऐसे में इन नियुक्तियों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफकांग्रेस संगठन को यह चुनौती है कि . कांग्रेस के मौजूदा विधायकों में से जिनको भी मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है। उन लोगों को यह नियुक्तियां देकर संतुष्ट किया जाए' । ताकि कांग्रेस और मजबूत हो सके। दूसरी तरफयह भी देखना जरूरी होगा कि आने वाले 'लोकसभा चुनाव में, प्रदेशभर के कांग्रेसी चेहरों में से कौन से ऐसे लोग हैं।ं जिनका लाभ आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है'। परंतु यहाँ एक समस्या और है जो कि कांग्रेस संगठन के सामने आने वाली है। यह कि प्रदेश भर में जो जो लोग इस बार का विधानसभा चुनाव किन्ही कारणवश हार गए हैं। वह भी इन नियुक्तियों की तरफटकटकी बांध कर देख रहे हैं। जिस से आलाकमान के लिए और भी मुश्किलें खड़ी होती नजर आने लगी हैं । अब कांग्रेस राज में आने पर कुछ न कुछ पा लेने के नजरिए से तो यह ठीक लगता है। परंतु कांग्रेस को इन हारे हुए विधायकों को नियुक्तियाँ देने से कोई खास लाभ नही होगा।

भाजपा ने अपने कार्यकाल में इस तरह की नियुक्तियों को लेकर सटीक कार्यप्रणाली को अंजाम देते हुए फैसले लिए थे। जैसे कि गत वसुंधरा राजे की सरकार ने भाजपा को अप्रत्यक्ष मजबूती प्रदान करने हेतु इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे संघ और भाजपा मानसिकता के लोगों को स्वतंत्रता का रक्षक करार देते हुए पेंशन तक शुरू कर दी थी। जिसकी वजह से संगठन को बल प्राप्त हुआ । ऐसे ही कई फैसलों की वजह से भाजपा भारी विरोध की हवा के बावजूद राजस्थान में जड़ से नहीं उखड़ पाई । भाजपा का प्रदर्शन उतना बुरा नहीं रहा है जितना कांग्रेसी सोच रहे थे। सट्टा बाजार में शर्तें लगाई जा रही थीं कि 150 सीटें आएंगी कांग्रेस की इस बार ।परंतु जब परिणाम आया तो नतीजा आप सभी के सामने है।

जब भाजपा इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारियां देने वालों को स्वतंत्रता का रक्षक बताकर सरकार द्वारा पेंशन लाभ के माध्यम से अपने साथ पुनः जोड़ सकती है। तो कॉन्ग्रेस ऐसा क्यों नहीं सोच पाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस के पास विचारधारा के समर्थकों की कमी है। बस कांग्रेस अपने झगड़ों के बीच सीधा देख नहीं पाती है' । वर्ना कांग्रेस के पास ऐसे सैकड़ों लोग आज भी है। जिन्होंने सन 1977.78 में इसी इमरजेंसी काल के विरुद्ध समीक्षा करवाती जनता पार्टी सरकार द्वारा स्व. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कई दिनों की जेल काटी है। शाह कमीशन द्वारा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के आदेश पारित होने पर पूरे देश से लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए गिरफ्तारियां दी थी। केवलअजमेर जिले से ही लगभग 450 लोग ऐसे रहे हैं।'

यदि कांग्रेस इन परिवारों में से भी उठा कर प्रदेश भर में राजनैतिक नियुक्तियाँ करती हैं। तो इसका अच्छा संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा सकता है। जो कांग्रेस हेतु बहुत ही श्रेयस्कर होगा। बजाये उन नेताओं को सरकार में नियुक्त किये जाने के जिनको कांग्रेस पहले ही कभी टिकट देकर तो कभी संगठन में जगह देकर संतुष्ट कर चुकी है। इस से कांग्रेस के शिथिल जनाधार को और मजबूती मिल सकती है। लेकिन तभी जब कांग्रेस लकीर से बाहर निकल कर इस तरह के फैसले ले। परंतु बजाय कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हेतु मजबूत करने के कुछ हारे हुए नेता गण प्रदेश भर में अपने विरोधियों को निपटाने हेतु हार की समीक्षा करवाने में जुटे हुए हैं। जिसका एक मात्र उद्देश्य बस 'खुद के विरोधियों को निपटाना ज्यादा है और कांग्रेस को मजबूत करना कम है' ।

वहीं भाजपा के सभी हारे जीते लोग पुनः लोकसभा हेतु मतदाता सूचियों की समीक्षा कर अपने समर्थकों के नाम जुड़वाने की योजना बना रहे हैं।

अजमेर ज़िले की कांग्रेस को लगा है स्व. इंदिरा गांधी की प्रतिमा का श्राप

नरेश राघानी

अजमेर। आज स्टेशन रोड से गुजर रहा था। तो अचानक निगाह पड़ी इंदिरा गांधी स्मारक पर स्थित स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर। जो कि लबादे में लिपटी अभी भी वहीं खड़ी थी। मेरे सहयोगी यश ने देख कर कहा, सर इंदिरा जी की प्रतिमा का श्राप लगा है अजमेर की कांग्रेस को अपने दिवंगत नेताओं की ऐसी बेकद्री करने वालों का यही हाल होता है।'

23 साल के एक युवा की निश्चल मन से कही गयी इस बात ने मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी मुझे लगा कि मैं यह बात आप लोगों तक भी पहुंचाऊं।

आपको बता दें कि इस प्रतिमा को लगाने के संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। यह प्रतिमा पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता के ऐतिहासिक योगदान से उनके द्वारा दो लाख रुपये देकर मंगवाई गई थी। और काफी समय तक अजमेर विकास प्राधिकरण के गोडाउन में पड़ी रही। रलावता ने बड़े संघर्ष और उठापटक के

चलते मुश्किल से इस प्रतिमा को इस स्थान पर लगावाया था। अब केवल उसका उद्घाटन मात्र ही बचा है। जो कि गत लोकसभा चुनाव से ही लंबित चल रहा है। तब शायद इस प्रतिमा ने सोचा होगा कि इतनी अच्छी भावना कांग्रेसियों ने दिखाते हुए इतना अच्छा काम किया है। चलो !!! इन्हें लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे देते हैं।और वाकई इस प्रतिमा का आशीर्वाद डॉ रघु शर्मा को लग गया और वह सांसद बना कर आये। रघु शर्मा के रूप में अजमेर के कांग्रेसियों को एक मजबूत सासद मिला। यही से अजमेर में पुनः कांग्रेस राज की स्थापना होती हुई दिखाई देने लगी।' उसके बाद कांग्रेस जन शायद भूल गए इस प्रतिमा का अनावरण करना।

फिर कुछ माह पहले ही एक बुजुर्ग और मानसिक रूप से विक्षिप्त भिखारी को जाने क्या सूझी उसने प्रतिमा को लबादे से आज़ाद किया और मिठाई खिलाकर खुद ही इस प्रतिमा का स्वेच्छिक अनावरण कर डाला । जिस पर सोशल मीडिया पर खबरें भी चली। लेकिन फिर भी अजमेर के कांग्रेसियों को शर्म नहीं आयी।

फिर सभी कांग्रेस जन विधानसभा चुनाव में लग गए और इंदिरा जी की प्रतिमा वहीं पर धूप और सर्दी में खड़ी रही। शायद लबादे में लिपटी यह सोचती रही कि . क्या इन लोगों के लिए मेरा कोई महत्व नहीं रह गया है। यही कांग्रेस जन जो आज इंदिरा जी की रॉयल्टी इतने सालों से राजनैतिक पदों पर आने के बाद मिले लाभ के रूप में खा रहे हैं उनको तनिक भी इस बात का लिहाज नहीं है कि इंदिरा गांधी स्मारक पर स्थित प्रतिमा का अनावरण करना कितना आवश्यक है।' शायद स्व. इंदिरा जी की प्रतिमा का यही भाव एक 'श्राप' के रूप में परिवर्तित होकर अजमेर की कांग्रेस को लग गया है । तभी शायद अजमेर की 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस हार बैठी है। जबकि प्रदेश भर में कांग्रेस की जीत हो चुकी है। और कांग्रेस की सरकार भी बन गयी है। परंतु अजमेर जिले के लगभग सभी नेता अब तक भी सत्ता सुख से वंचित है।' अब तो यही नजर आ रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव भी कहीं इंदिरा जी की प्रतिमा के श्राप की जद में ना आ जाए।

इसलिए कांग्रेस जनों के लिए लाभकारी बात यही होगी कि स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी स्मारक की मूर्ति का अनावरण तुरंत प्रभाव से करवा दिया जाए। अन्यथा लोकसभा चुनाव कांग्रेस चाहे पूरे राज्य में जीत जाए।परंतु अजमेर में कांग्रेस का इस श्राप की वजह से जीत पाना मुश्किल ही नजर आएगा।

'आप खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो दुकान जाकर खूब धन कमाएंगे धन कमाएंगे तो हमारे जैसा कोई आएगा और'

'झूलेलाल क्रिकेट लीग के समापन के दौरान फिसली मेयर धर्मेंद्र गहलोत की जुबान'

नरेश राघानी

अजमेर। वैसे तो हमारे मेयर धर्मेंद्र गहलोत बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन उनके भाग्य में हमेशा से ही प्रसिद्धि ऐसे ऐसे कोनों से आती है कि बस पूछिये मत। मैं मेयर साहब की कार्यशैली का व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़बरदस्त वाला फैन हूँ। मेयर का स्वभाव भी बहुत मिलनसार है। लेकिन आज उन्होनें मौज मस्ती में ही सही। सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसा कह दिया जो वहाँ बैठे लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगा।' जगह और आयोजन आपको बताऊंगा तो शायद आपके और भी स्पष्ट रूप से समझ आ जायेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 'तो साहब!!!! जगह थी लोको ग्राउंड और मौका था एसिन्धी समाज के युवाओं द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता झूलेलाल प्रीमियर लीग के समापन समारोह का मंच।'

जहाँ पर सिन्धी समाज के लगभग सभी सम्मानित चेहरे मौजूद थे। जिनमें 'विधायक वसुदेव देवनानी, अनीता भदेल सहित कामल प्रकाश किशनानी, गिरधर तेजवानी, नरेन साहनीए हरि चंदनानी, गिरधर तेजवानी रमेश टिलवानी, गिरीश लालवानी, रश्मि हिंगोरानी मनोहर मोटवानी गिरीश असनानी सहित सैकड़ों चर्चित सिन्धी हस्तियाँ मंचासीन थी।'

इन सभी के मध्य खड़े होकर अपने उदबोधन के दौरान मेयर साहब सिन्धी समाज की तारीफकरते करते यह कह गए कि .

'आप खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो दुकान जाकर खूब धन कमाएंगे। धन कमाएंगे तो हमारे जैसा कोई आप के पास आएगा और 'अपुन भी वहीं पर कहीं साइड में ही पड़े हुए थे। अपुन की तो रहने दो वहां मौजूद देवनानी के कई शुभचिंतकों को यह समझ नहीं आया कि इज्ज़त दी जा रही है या ली जा रही है। मतलब सिन्धी समाज को सरे आम गहलोत द्वारा शायद प्रेरणा दी जा रही थी कि . आप खेल कूद कर स्वस्थ रहिए और नेताओं के लिए पैसे कमा कर मस्त रहिए। 'मेरे पीछे बैठी समाज की एक पुरानी दुनाली बंदूक तो जैसे मारे रोष के घुटघुटा उठी। मैंने हाथ थाम कर कहा . दादा !!! क्यूँ फड़फड़ा रहे हो बेवजह। आप तो पुराने सहयोगी रहे हो निगम और मेयर साहब के। रहने दो न यार कोई आया है अपने समारोह में इज्ज़त से बिठाओ और अपनी शालीनता का परिचय दो। दादा बोले ए भाई !! ही नेता असांखे लंगी ता समझन छा। ये नेता हमें लंगी समझते हैं क्या ' मैंने भी तपाक से बोल दिया कि . 'हाँ और क्यूँ न समझे बताओ। आप लोगों ने इतने सालों में सिवाय दुकान खोल कर बंद करने के और किया क्या है । व्यापारी कौम घोषित हो चुके हो । तो लोग व्यापारी ही कहेंगे न। फिर क्या बुरा कर दिया यदि गहलोत ने आपको व्यापारी की तरह ट्रीट करके बतौर नेता आप लोगों को आर्थिक सहयोग करने वाला मान लिया तो हिम्मत है तो आइए राजनीति में और पाइए सफलता। यूँ बस व्यापार करते रहेंगे तो यही होगा। क्यूँ केवल चेटीचंड के दिन लाखों रुपया खर्च कर देते हो क्यूँ नहीं बनाते समाज के सहयोग से चंदा करके राजनैतिक फण्ड । जो कि सिन्धी समाज की उभरती राजनैतिक प्रतिभाओं को समर्थन देकर चुनावी मैदान में जीत दर्ज करवाएँ। और आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें' । सुनकर दादा निरुत्तर हो गए। समारोह का समापन हो गया सिन्धी युवाओं के साथ देवनानी एमेयर साहब, अनिता भदेल और वही दादा भी नाच गा कर घर चले गए। आफिस पहुँचा तो 'मेरा मोबाइल टुन टुनाने लगा' । मैंने कॉल उठायी तो उस तरफवही दादा बोले . 'नरेश जी !!! मुझे मेरे सिन्धी मित्रों में केवल आप ही ऐसे पत्रकार दिखाई दिए जो सब कुछ खरा खरा लिख और बोल लेते हो। कृपया मेरी यह भावना यदि आपके ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देंगे तो मुझे खुशी होगी। ईश्वर आपको शक्ति दे।' पहले तो मैं बहुत देर तक दादा की बातें निशब्द सुनता रहा।और सोचता रहा कि यदि इतना बुरा लगा दादा को तो वह खुद क्यूँ नाच रहे थे ।

'खैर !!! फिर मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है दादा !! मैं आपकी भावना मेरे ब्लॉग के माध्यम से मेयर साहब तक पहुंचा दूंगा' । सो यह बातें लिखकर मैंने दादा से किया हुआ वादा निभा दिया है।

ताकि एक बुजुर्ग को यह ना लगे कि मैंने उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। 'यदि किसी को मेरी यह बात मनघड़न्त लग रही हो तो वह आ जाये मेरे पास मैं उनकी दादा से भेंट करवा दूंगा।'

राफेल जांच से बचने के लिए ही आलोक वर्मा को पद से हटाया गया था- संजय सिंह

नयी दिल्ली। आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि सीबीआई निदेश पद से आलोक वर्मा को हटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के मंगलवार के फैसले से साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल घोटाले में जांच से बचने के लिए वर्मा को पद से हटाया था। सिंह ने सरकार की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और नियम विरुद्ध बताते हुये कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी का प्रभार प्रधानमंत्री के पास है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी डीओपीटी के अधीन आती है जिसका असंवैधानिक तरीके से उपयोग करने की कोशिश की गयी।

सवर्ण आरक्षण विधेयक 323 मतों से पारित मोदी ने कहा ऐतिहासिक क्षण

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरियों और शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पारित होने पर इसे देश के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण करार दिया। लोकसभा में यह विधेयक पारित होने के बाद किए गए ट्वीट में मोदी ने कहा कि इसने एक ऐसे प्रभावी उपाय को हासिल करने की प्रक्रिया को गति दी है जिससे समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा।मोदी ने कहा यह सुनिश्चित करना हमारा प्रयास है कि हर गरीब व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय का हो गरिमापूर्ण जीवन जिये और उसे हर संभव मौके मिलें। प्रधानमंत्री ने इस विधेयक का समर्थन करने वाली हर पार्टी के सांसदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा हम निश्चित तौर पर सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी। अब यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में जायेगा जहां उच्च सदन की बैठक एक दिन और बढ़ा दी गयी है। लोकसभा में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने संविधान 124 वां संशोधन 2019 विधेयक का समर्थन किया। साथ ही सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है। लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरीबों की सरकार होने की बात कही थी और इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया।

सम्पादकीय

राम मंदिर, राफेल और राहुल ने चुनावी वर्ष में बढ़ा दीं मोदी की मुश्किलें

वर्ष 2019 में राम राहुल और राफेल तीन ग्रह एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुण्डली में बैठे दिखाई दे रहे हैं। चुनावी वर्ष में इन तीन ग्रहों का एक साथ एक घर में बैठना मोदी के राजनैतिक भविष्य के लिए अशुभ एवं अप्रिय स्थितियां पैदा कर सकता है। राम मंदिरए राफेल डील और राहुल गांधी तीनों परस्पर विरोधी ग्रह हैं। तीन शत्रु ग्रह अगर किसी की भी कुण्डली में एक साथ बैठ जाएं तो मुश्किलें बढ़ना तय माना जाता है। फ्लिवक्त नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कुण्डली इन तीन ग्रहों के अनिष्ट दुर्योग से बुरी तरह प्रभावित दिख रही है। राम मंदिर का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो वहीं राफेल पर कांग्रेस च्चौकीदार चोर हैष् का नारा बुलंदी से लगा रही है। राहुल गांधी पिछले एक.डेढ़ वर्ष में मोदी से टक्कर लेने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में राम मंदिरए राफेल डील और राहुल गांधी ने फ्लिवक्त मोदी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मोदी अशुभ ग्रहों का संकट बखूबी महसूस कर रहे हैंए और शायद वो इनकी काट भी खोज रहे हों।

भारतीय जनता पार्टी आज जिस भव्य स्वरूप और राजनीतिक हैसियत में हैए उसके पीछे राम मंदिर मुद्दे का सबसे बड़ा योगदान है। दो सांसदों से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने तक जब.जब भाजपा संकट में पड़ीए उसे राम नाम ने ही सहारा दिया। भाजपा राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। लेकिन आज ये मुद्दा ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका हैए जहां भाजपा को इस मामले में कोई बड़ा व ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज केन्द्र और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है। भाजपा के सामने एकतरफदेश की वो जनता है जिसने उसे राम मंदिर के मुद्दे पर उसे समर्थन और वोट दिया तो दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट है जहां मामले की सुनवाई लंबित है। अर्थात् इस मुद्दे पर भाजपा की स्थिति आगे कुआंए पीछे खाई वाली है। राम मंदिर के मुद्दे पर टाल.मटोल से भाजपा के सहयोगीए हिंदूवादी संगठन और खासकर आरएसएस में भी नाराजगी का माहौल है। असल में एससी.एसटी एक्ट में अध्यादेश लाकर मोदी सरकार ने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ायी हैं। ऐसे में राम भक्त दलील दे रहे हैं कि राम मंदिर पर भी सरकार अध्यादेश लाये। पिछले दो.तीन महीने से यह मुद्दा दोबारा चर्चा में है। साधु.सन्तए आरएसएसए वीएचपी से लेकर राम भक्त राम मंदिर निर्माण के लिये मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। राम मंदिर पर सरकार की हीला.हवाली से भाजपा के समर्थक नाराज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अदालत के फैसले के बाद ही कोई कदम उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही नयी बेंच बनाकर सुनवाई तय करेगा। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैए ऐसे में भाजपा की हालत मशहूर फ्लिम शोले के उस हाथ कटे ष्ठाकुरष् जैसी हैए जो चिल्ला तो सकता थाए लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता था।

राम मंदिर की भांति राफेल डील के मामले ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मोदी सरकार के अब तक कार्यकाल में कांग्रेस को ष्राफेल डीलष् ही एकमात्र ऐसा अस्त्र मिला हैए जिससे वो मोदी सरकार को घेर पा रही है। सड़क से लेकर संसद और चुनावी मंच से लेकर चर्चाओं तक में कांग्रेस राफेल.राफेल चिल्ला रही है। प्रधानमंत्री के बयानए वित्त मंत्री की फटकार और रक्षा मंत्री के ष्निर्मल ज्ञान और धुलाईष् के बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी खरीद की प्रक्रिया पर सरकार को क्लीन चिट दे चुका है। राहुल का आरोप है कि देश का पैसा पीएम मोदी ने अनिल अंबानी के जरिए चोरी करवाया। एचएएल से 30 हजार करोड़ का अनुबंध तोड़कर अनिल अंबानी को दे दिया गया। जिसके चलते देश के प्रतिभाशाली नौजवानों का रोजगार छिन गया। राहुल के मुताबिक राफेल डील पर अगर मुकम्मल जांच होती है तो दो घोटालेबाजों का नाम निकलेंगे। जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और अनिल अंबानी का नाम शामिल होगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इस मुद्दे पर सिलसिलेवार जवाब दे चुकी हैं। बावजूद इसके कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है।

राफेल मामले में मोदी पर बरसे राहुल कहा. पीएम को जांच से कोई नहीं बचा सकता

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल मामले की जांच से कोई नहीं बचा सकता और पूरे देश को पता चलेगा कि मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपये अपने मित्र अनिल अंबानी को दे दिए। संसद भवन परिसर में गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे।

उन्होंने कहाए ष्सीबीआई प्रमुख को रात में एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अब न्यायालय के फैसले से हमें कुछ राहत मिली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहाए सीबीआई प्रमुख बहाल हो गए हैं। वे प्रधानमंत्री इस मामले की जांच से भाग नहीं सकते यह असंभव है। मोदी जी चर्चा से भाग गए। उन्हें राफेल मुद्दे पर जनता की अदालत में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें राफेल मामले ;की जांच से नहीं बचा सकते। ;वह कोई भी चर्चा से भाग नहीं सकते।इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा वह ;मोदी सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा मोदी जी कृपया याद रखिए कि सरकारें आती.जाती हैं। हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग ;सीवीसी की जांच पूरी होने तक वर्मा केए कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगा दी है।

अय्यर के बिगड़े बोल पूछा. दशरथ के महल में 10000 कमरे थे तो राम कौन.से में पैदा हुए

नई दिल्ली।अपने विवादित बयानों से कांग्रेस का सिरदर्द पैदा कराने वाले मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। अय्यर ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि अयोध्या के राजा दशरथ के महल में 10 हजार कमरे थे और यह किसी को पता नहीं है कि भगवान राम कौनसे कमरे में पैदा हुए थे उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि आप बेशक मंदिर बनाइए मगर आप यह कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे।

दिल्ली में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफइंडिया के तरफसे आयोजित एक समारोह एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम में मणिशंकर अय्यर बोल रहे थे। 6 दिसंबर को पतन वाला दिन बताते हुए उन्होंने नरसिंहा राव की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया। इससे पहले अय्यर ने गुजरात चुनाव के समय पीएम मोदी के बारे में नीच शब्द का इस्तेमाल किया था जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। 2018 में अय्यर का निलंबन वापस ले लिया गया था।

शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते असामान्य लोकसभा चुनावों के लिए नहीं होगा गठबंधन

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच द्वंद्व शुरू हो गया हैए पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ अकेले एक कमरे में मुलाकात की थी। जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिनए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगातार बीजेपी को राफेल मामले में निशाने पर लिए जाने के बाद से देखा जा रहा है कि शिवसेना अब बीजेपी को आंख दिखा रही है। पिछले दिनों शिवसेना प्रमुख ने राफेल पर जेपीसी बनाए जाने का समर्थन किया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए चौकीदार का नारा अपनी रैलियों में लगवाया। हालांकिए इसके बाद भी बीजेपी ने नरम रुख अख्तियार करते हुए उद्धव ठाकरे के बयानों को नजरअंदाज किया।

इसी बीच अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रदेश की 48 में से 40 सीटें हमें जीतनी है। जिसके बाद अमित शाह ने भी इस बयान का उल्लेख किया। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना नाता समाप्त कर दिया। विशेषज्ञों ने माना था कि करीब ढाई दशक से एक साथ काम कर रही शिवसेना के भीतर इतना आत्मविश्वास भर गया था कि वह प्रदेश की आधी सीटें आसानी से जीत सकती है। हालांकि चुनाव नतीजों में साफ हो गया और शिवसेना के खेमे में 18 सीटें आई। बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में छप रहे लेखों से यह तो साफ हो गया कि भले ही शिवसेना ने चुनावों के बाद बीजेपी को समर्थन देकर देवेंद्र फड्णवीस को प्रदेश की सत्ता सौंप दी हो लेकिन वह खुद को इसके काबिल मानते थे। जून के पहले सप्ताह में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में संपर्क फॉर समर्थन के मुहीम के जरिए भाजपा प्रमुख अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस ने मुलाकात की। यह मुलाकात एक कमरे में हुई जहां पर इन तीनों नेताओं के अलावा आदित्य ठाकरे मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते सामान्य हो गए।

जून में हुई मुलाकात से पहले फरवरी में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए। इन चुनावों के बीच में बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सामना पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगाई। बीजेपी ने यह पत्र लिखा ही था कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने में लेते हुए कहा कि क्या बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड्णवीस का मुंह बंद करा पाएगी।सामना में छप रहे लेख में ऐसे ही बयानों के ढेर लग गए। हालांकि जब दोनों राजनीतिक दलों की मुलाकात हुई तो सामना में ठाकरे की तर्ज पर लेख छपा कि सरकार को सत्ता संभालते हुए चार साल बीत गए और उनके पास राजग के साथ मुलाकात करने का वक्त था मगर हमारे साथ नहीं। वहींए इस मुलाकात को चुनावी रणनीति करार दिया और यह दर्शा दिया कि एक बार फिर वह आने वाले लोकसभा चुनावों में अपने दम पर प्रदेश की सीटें हासिल करेंगे।

कई बार ऐसे मौके सामने आए जहां पर कांग्रेसी नेताओं एवं कांग्रेस के साथ की राजनीतिक पार्टियों के समर्थन पर सामना मे लेख छपा। अमित शाह द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सवाल खड़ा करने के बाद सामना ने लिखा कि चुनावों के दौरान सोशल मीडिया के जरिए जनता को बरगलाने के बाद आज उपदेश देने आई है बीजेपी। पिछले साल अक्टूबर में सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी एक नया कानून ले कर आ रही थी। जिसके बाद सामना ने लिखा कि बीजेपी ने विरोधियों की बदनामीए अवमानना और दुष्प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और पर्दाफाश होने के बाद कानून की बात कर रही है।इसी के बाद शिवसेना ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का समर्थन करते किया और पवार का बयान छापा कि अभिव्यक्ति की आजादी वाले युवकों अपने विचार व्यक्त करते समय अपना एक पैर कारागृह में रखकर सोशल मीडिया में बोलते रहो।ऐसे कई मौके आए जब शिवसेना ने कांग्रेसियों का या फिर उनसे वास्ता रखने वाले राजनीतिक पार्टियों का समर्थन किया हो। हाल ही में राफेल मामले में कांग्रेस का समर्थन करते हुए जेपीसी की मांग की। उससे पहले राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहने वाले बयान का उपयोग अपनी रैलियों में करते हुए देखे गए।विशषज्ञों का मानना है कि पांच रा'यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश में बीजेपी की छवि धूमिल हुई है एवं 2019 के चुनावों में बीजेपी एवं उनके साथी पार्टियों को काफी नुकसान होने वाला है। ऐसे में शिवसेना अपने दम पर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहेगी और फिर चुनावों के बाद स्थिति को टटोलते हुए उस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती हैए जिसकी सरकार बनने के आसार हों।

मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक शिवसेना के सांसदों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए और मिलकर चुनाव लड़ना चाहिएए तभी हम सभी सीटों को जीत पाएंगे। जबकि शिवसेना के रा'यसभा सांसदों की माने तो उनका साफकहना है कि प्रदेश में इस बार हमें किसी के साथ गठबंधन करने की जरुरत नहीं है। पिछले लोकसभा चुनावों की तर्ज पर इस बार भी हमें अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए शिवसेना के भीतर फूट पड़ सकती है और जैसा देखा गया कि दल.बदल का खेल शुरू हो सकता हैं।

लोकसभा चुनाव की जल्दबाजी में बीजेपी ने लाया आरक्षण बिल- कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा में सामान्य वर्गो के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी में लाने की कवायद करार दिया और कहा कि इसमें कानूनी त्रुटियां हैं। संविधान 124वां संशोधन विधेयक पर मंगलवार को चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस सदस्य के वी थामस ने कहा कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया और 48 घंटे के अंदर इसे सदन में चर्चा के लिये लाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी विधेयक की अवधारणा का समर्थन करती है।थामस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसे जल्दबाजी में पेश करने से अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। इसे ष्तमाशाष् नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1991 में तत्कालीन नरसिंह राव सरकार ने ऐसा एक प्रयास किया था लेकिन यह उच्चतम न्यायालय में नहीं टिक पाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसे देश के 50 प्रतिशत रा'यों में स्वीकृति की जरूरत होगीए और सरकार के पास तीन महीने का समय बचा हैए तो इस अवधि में क्या सभी प्रक्रियाएं पूरी होंगी।

उन्होंने कहा कि देश ने नोटबंदी को देखा है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह आर्थिक कल्याणए फर्जी मुद्रा पर लगाम लगाने से जुड़ा है। लेकिन आज की स्थिति क्या हैए सामने है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानूनी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा है। थामस ने कहा कि विधेयक में रोजगार के संबंध में आरक्षण प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने कहा था कि हर साल दो करोड़ नौकरियां सृजित की जायेंगी। लेकिन रोजगार सृजन की स्थिति बेहद खराब है। एक रिपोर्ट के अनुसारए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सबसे अधिक कमी का सामना करना पड़ा हैॅउन्होंने कहा कि एक तरफ कानूनी त्रुटियां हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की दर काफी उच्च है तो इस स्थिति में इसे लागू करने में समस्याएं आयेंगी। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि तीन रा'यों में पराजय के कारण सरकार अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इसे लाई है।

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास कांग्रेस-टीएमसी का सदन से वॉकआउट

नयी दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को पारित नागरिकता संशोधन विधेयक को भाजपा ने जहां पाकिस्तानए अफगानिस्तानए बांग्लादेश से विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन एवं सिख अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि विधेयक में कमियां हैं और यह बांटने वाली प्रकृति का है। संसद की संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा शुरू होने पर सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें कई कमियां हैं। इसे विचार के लिये प्रवर समिति के पास भेजा जाए।उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक मामला है और इस पर और पड़ताल की जरूरत है। यह असम समझौते की भावना के अनुरूप नहीं है। इसके बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस की सुष्मिता देव का नाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिये पुकारा। इस दौरान विधेयक को पेश किये जाने के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि यह बांटने की प्रकृति वाला विधेयक है। इससे असम में अशांति फैल रही है। दिल्ली में गृह मंत्री को पता नहीं है लेकिन वह इस बारे में बताना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर संसद की समिति में विचार किया गया लेकिन आमसहमति बनाने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें अफगानिस्तानए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिन्दूए बौद्धए जैनए पारसीए सिख और ईसाई धर्म के लोगों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कम संख्या में अल्पसंख्यक आए हैए इन दोनों देशों से आए लोगों को नागरिकता दें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश को इससे हटा दिया जाए। विधेयक का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए।

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के एस एस अहलूवालिया ने कहा कि बांग्लादेशए पश्चिमी पाकिस्तान से जो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैंए उन देशों के अल्पसंख्यकों के लिये यह विधेयक लाया गया है। बीजद के बी महताब ने विधेयक के दायरे से बांग्लादेश को हटाये जाने की मांग करते हुए कहा कि जब श्रीलंका को इसमें शामिल नहीं किया गया है तो बांग्लादेश को क्यों शामिल किया गया है जहां से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। बीजद नेता ने यह भी कहा कि पाकिस्तान समेत अन्य देशों के अल्पसंख्यक हिंदू भारत में नहीं आएंगे तो कहां जाएंगेघ् शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने के बाद इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए।

माकपा के मोहम्मद सलीम ने कहा कि यह विधेयक समस्या का समाधान नहीं हैए इससे नयी समस्या पैदा होगी। असम में आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने विधेयक पर विरोध जताते हुए कहा कि धर्म और भाषा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। सलीम ने आरोप लगाया कि ऐसा करके कानून नहीं बनाया जा रहाए बल्कि 2019 के चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र लिखा जा रहा है। सपा के मुलायम सिंह यादव ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान और असम समझौते के खिलाफहै।

भाजपा की विजया चक्रवर्ती ने कहा कि यह विधेयक असम के लोगों के लिए संजीवनी है और मूल निवासियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से असम में आबादी का अनुपात असंतुलित हो गया है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विधेयक को ष्संविधान के खिलाफष् बताते हुए कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि भारत इजराइल नहीं है जहां धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाए। भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है तथा उनकी आबादी वहां घट गईए जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है।

राहुल गांधी जयपुर में

किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित

जयपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को सुबह ग्यारह बजे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार सभा स्थल पर बनाए गए मंच पर राहुल गांधी के साथ लगभग दो दर्जन नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है।

मंच पर प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट, वरिष्ठ नेता सीपी जोशी, गिरिजा व्यास, सहप्रभारियों सहित कई पूर्व अध्यक्षों को मंच पर जगह मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली से आए केन्द्रीय नेता भी मंच पर मौजूद रहेंगे। सभा स्थल को तीन भागों में बांटा गया है। पहले ब्लॉक में मंत्री, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। दूसरे ब्लॉक में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिलाध्यक्षों एवं अन्य नेताओं को बैठाया जाएगा। तीसरे ब्लॉक में महिला नेताओं और महिला कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की है।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बरकरार, एक ही दिन में तीन और मौतें

जयपुर। नए साल की शुरुआत से ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और इसका असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस जानलेवा बीमारी के चलते मंगलवार को भी अलग-अलग स्थानों पर तीन मरीजों की मौत हो गई। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वाइन फ्लू के चलते मंगलवार को जोधपुर, नागौर और जालौर में एक-एक मरीज की मौत हो गई। उधर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का अभी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसके साथ नए साल के आठ दिनों में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। प्रदेशभर में मंगलवार को 221 सेंपल जांच के लिए भेजे गए इनमें से 57 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसी के साथ अब प्रदेश में 341 पॉजेटिव मरीज हो चुके हैं। वहीं मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के एक नेता भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम प्रयास हुए फेल स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए जहां मंत्री रघु शर्मा भी चिंतित हैं वहीं स्वास्थ्य महकमे की भी नींद उड़ी हुई है। नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने और मरीजों की मौत से इन दिनों स्वास्थ्य विभाग में हडकंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी आए दिन बैठकें कर रहे हैं पर विभाग की ओर से किए जा रहे तमाम प्रयासों का स्वाइन फ्लू की रोकथाम पर कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है।

संविदा कर्मियों की समस्याओं का निराकरण होगा- कल्ला

जयपुर। प्रदेश के संविदाकर्मियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक में सारे विभागों को इन कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए हैं। कमेटी संयोजक ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने इन संविदाकर्मियों की स्थिति को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया था और वे सिर्फ वादे ही करते रहे, लेकिन हमारी सरकार इनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ हल करने का प्रयास करेगी। कल्ला ने मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों को संबंधित विभागों के संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। यह भी जानकारी मांगी गई है कि संविदा कर्मियों की संख्या के साथ कितनी अवधि से कार्यरत हैं। संविदा कर्मियों के बारे में चल रहे कोर्ट केसेस में क्या स्थिति है। इन संविदा कर्मचारियों को लेकर संबंधित विभागों ने अब तक क्या कार्रवाई की और क्या प्रगति हुई है। बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना सहित एसीएस वित्त निरंजन कुमार आर्य, एसीएस रोहित कुमार सिंह, कार्मिक प्रमुख सचिव रोली सिंह, स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव भास्कर सावंत भी बैठक में मौजूद रहे।

केन्द्र से इंतजार, मूंगफली खरीद की पांच दिन बाद अवधि खत्म

जयपुर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि पांच दिन बाद खत्म हो रही है। राज्य सरकार की ओर से पत्र लिखकर केन्द्र से 31 जनवरी तक अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया है, लेकिन अभी केन्द्र की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में राज्य सरकार को केन्द्र की स्वीकृति का इंतजार है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली का बेचान करने वाले 19 हजार 864 किसानों के खातों में अब तक 230 करोड़ का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है। शेष किसानों को जल्द ही भुगतान करवाया जा रहा है। राज्य में मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 11 अक्टूबर से तथा मूंगफली की 16 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है और अब तक 2 लाख 49 हजार 938 किसानों से 2802.01 करोड़ मूल्य की उपज की खरीद की जा चुकी है। मूंगफली खरीद 13 जनवरी को खत्म हो रही है, इसे 31 जनवरी तक जारी रखने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को पत्र लिख कर अनुरोध किया है। राजफैड के प्रबंध निदेशक ज्ञानाराम ने बताया कि प्रदेश में राजफैड द्वारा 300 खरीद केन्द्र स्थापित कर की जा रही मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिए 4 लाख 56 हजार 51 किसानों ने अपना ऑनलाइन पंजीयन करवाया है।

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दे आरयू

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से केमेस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दे। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. विजय बेनीवाल व 4 अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो याचिकाकर्ताओं का चयन मई 2018 में होने के बाद अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विवि में बिना असिस्टेंट प्रोफसर के इस विषय की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। याचिका में अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी ने अदालत को बताया कि विवि प्रशासन ने 22 मई, 2017 को असिस्टेंट प्रोफसर के पांच पदों सहित अन्य पदों के लिए भर्ती निकाली थी। भर्ती में याचिकाकर्ताओं का चयन कर लिया गया। वहीं सलेक्शन कमेटी ने भी उनकी नियुक्ति की सिफारिश कर दी। जिसे सिंडीकेट ने गत 29 मई को अप्रूव्ड भी कर दिया।

जिला कलक्टर ने किया भिनाय क्षेत्र में कार्यालयो का निरीक्षण

चिकित्सकों को दिए एप्रीन पहनने के निर्देश

अजमेर, 08 जनवरी। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने मंगलवार को भिनाय एवं बिजयनगर क्षेत्रा में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया।जिला कलक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिनाय के निरीक्षण में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर को जानवरों एवं सुअरों से मुक्त करने के लिए कार्यवाही अमल में लायी जाए। साथ ही समस्त स्टाफ को एप्रीन पहनने के लिए पाबंद किया। मौके पर एप्रीन नहीं पहनने वाले चिकित्सकों एवं कार्मिकों को नोटिस जारी करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी को निर्देश प्रदान किए। मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त दवाएं मरीजों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। दवाओं की अग्रिम मांग भेजकर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अवधि पार दवाओं के निस्तारण की नियमानुसार व्यवस्था हो। चिकित्सालय में लगे ओटो जनसेट की मरम्मत करवाकर उसे तुरन्त उपयोग योग्य बनाया जाए। चिकित्सालय की प्रयोगशाला की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाने के लिए कहा। उन्होंने बिजयनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 6 बिस्तरों के आपातकालिन वार्ड को आरम्भ करने के लिए निर्देश प्रदान किए। इसके लिए अस्पताल के मुख्य भवन के प्रवेश द्वार के पास के ही कमरे को विस्तार दिया जाए। चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था, ड्यूटी रोस्टर रजिस्टर संतोषजनक पाए गए। बेकार एवं मरम्मत नहीं होने वाले सामान को निलाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अतिरिक्त बिस्तरों एवं पलंगों को निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित करने के लिए कहा। पूराने क्षतिग्रस्त क्वार्टर्स एवं रसोईघर को निर्धारित प्रक्रिया से गिरवाया जाएगा। इनके स्थान पर नए भवन एवं बगीचा विकसित किया जाएगा। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा शल्यक्रिया पुनः आरम्भ करने की जानी चाहिए। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रक्त की आपूर्ति जिला स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। श्री शर्मा ने अमरगढ़ तथा करांटी में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। अमरगढ़ में गणेश डूंगरी रोड पर ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य देखा। यहां कार्य लाइनिंग करके तथा समूह बनाकर करना पाया गया। मेडिकल किट में समस्त दवाएं सही पायी गई। श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए निर्धारित टास्क समय पर पूर्ण करने के लिए कहा गया। इसी प्रकार करांटी में नाड़ी निर्माण कार्य का अवलोकन कर कैचमेंट एरिया का जायजा लिया। श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए विकास अधिकारी श्री अमित कुमार शर्मा को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

जिला कलक्टर से मोतीपुरा गांव के ग्रामीणों ने गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण के संबंध में समस्या रखी। ग्रामीणों ने बांदनवाड़ा से मोतीपुरा गांव तक 2 किलोमीटर की सड़क को निविदा में प्रदान की गई, शर्तों के अनुसार उच्च गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने के लिए निवेदन किया। जिला कलक्टर ने ग्रामीणो को संबंधित विभाग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त कार्य सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने भिनाय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण कर भूमि अवाप्ति का अवार्ड वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी श्री नंद किशोर राजौरा को निर्देश दिए। साथ ही सतर्कता समिति, सीएलजी की बैठकें एवं जनसुनवाई नियमित करने के लिए कहा। उपखण्ड कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण करने तथा क्षतिग्रस्त पशु चिकित्सालय के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बिजयनगर तहसीलदार कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां मॉर्डन रिकार्ड रूम का निरीक्षण किया। ई धरती सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन अपडेशन के कार्य का निरीक्षण किया। कार्य संतोषजनक पाया गया। पूर्व निरीक्षणो में बने ऑडिट पैरा का निस्तारण करने के लिए कहा गया। इस संबंध में फाईलें मसूदा तहसील से मंगवाकर उनको निस्तारित किया जाए। भू राजस्व वसूली को शत प्रतिशत करने के लिए स्थानीय तहसीलदार श्री प्रभात त्रिपाठी को निर्देशित किया गया।

उन्होंने पुलिस थाना बिजयनगर का निरीक्षण कर चोरी रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए उप पुलिस अधीक्षक श्री गिरधर सिंह को निर्देश दिए। पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों की पंजीका का संधारण करने के लिए कहा। उन्होंने मालखाने एवं शस्त्रागार का अवलोकन कर हथियारों की सुरक्षा व्यवस्था जांची। इन अवसरों पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग, अधीक्षण अभियंता श्री कबीर अख्तर, जिला परियोजना अधिकारी श्री एस.के.सिंह सहित स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

एलईडी बल्ब युक्त फिलामेंट बल्ब मुक्त डिस्कॉम- भामू

अजमेर, 8 जनवरी। प्रबंध निदेशक बी. एम. भामू ने बताया कि कार्यकाल ग्रहण करने के पश्चात् डिस्कॉम की आर्थिक, भौगोलिक स्थिति का गहन अध्ययन व मनन किया गया जिसमें डिस्कॉम के आदिवासी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या प्रबंधन के सामने आई कि आदिवासी क्षेत्रा में अधिकांश लोग घरों में फिलामेंट बल्ब का उपयोग करते है जिससे उनका विद्युत खर्च अधिक होता था और वे विद्युत बिल का भुगतान नहीं कर पाते थे जिससे विद्युत चोरी की घटनाएं भी काफी अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही थी।प्रबंध निदेशक ने बताया कि उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु मेरे द्वारा एक अभियान का आव्हान डिस्कॉम अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किया गया जिसको मैंने ''एलईडी बल्ब युक्त फिलामेंट बल्ब मुक्त अभियान'' नाम दिया जिससे आदिवासी क्षेत्रा के अन्दर रहने वाले गरीब व पिछड़े तबके के परिवारों के घरों में फिलामेंट बल्ब उतारकर उसके स्थान पर एलईडी बल्ब लगाने की मुहिम प्रारम्भ की गई जिसका आगाज 27 अप्रेल, 2018 को किया गया। प्रबंध निदेशक बी. एम. भामू द्वारा गरीब तबके के परिवार जिनके पास एलईडी बल्ब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध नहीं होता, को देखते हुए एक नवाचार 100 वाट से 9 वाट यानि एलईडी बल्ब युक्त फिलामेंट बल्ब मुक्त अजमेर डिस्कॉम करने की मुहिम चलाई जिसमें अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा स्वयं भामाशाह बनकर 1,25,000 एलईडी बल्ब खरीदकर टीएसपी क्षेत्रों में गरीब तबके के परिवारों के यहां से फिलामेंट बल्ब उतारकर उसकी जगह 9 वाट का एलईडी बल्ब लगाए गए।

प्रबंध निदेशक द्वारा आव्हान करने पर अभी तक 2 लाख 75 हजार एलईडी बल्ब भामाशाहों एवं उपभोक्ताओं द्वारा भी फिलामेंट बल्ब की जगह बदलने हेतु सहयोग के रूप में प्रदान की है। अभी तक कुल 4 लाख एलईडी बल्ब फिलामेंट बल्ब की जगह लगा दिए गए है। इस अभियान से गरीब तबके के जो परिवार 100 के फिलामेंट बल्ब की वजह से बिजली का बिल अधिक प्राप्त कर रहे थे और उसका भुगतान करने में असमर्थ थे उनके विद्युत खपत में महत्वपूर्ण कमी आई है जिससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ प्राप्त हुआ और अधिक विद्युत खर्च के कारण जब उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं कर पाता था तो उसके विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता था, इस कारण उपभोक्ता के विद्युत चोरी करने की संभावना बढ़ जाती थी। इस अभियान से उपभोक्ताओं को तो प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ ही है साथ ही अजमेर डिस्कॉम को भी विद्युत चोरी रोकने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ डिस्कॉम का पीक आवर्स में लोड कम हुआ है जिससे महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती है एवं डिस्कॉम की छीजत में भी कमी आई है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में निगम का वित्तीय 130355 करोड़ रूपए था जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह घटकर 382.82 करोड़ रूपए आ गया है। इस तरह घाटे में निरन्तर कमी लाकर 920.73 करोड़ का घाटा कम कर दिया गया है। घाटे में कमी आने का एक कारण प्रबंध निदेशक के नवाचार 100 वाट से 9 वाट भी है जिसका घाटे के निरन्तर कमी लाने में अहम योगदान रहा है।

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ,मसूदा क्षेत्रा में 31 लाख के 9 कार्य स्वीकृत

अजमेर, 08 जनवरी। जिले के मसूदा पंचायत समिति क्षेत्रा में मगरा क्षेत्राीय विकास कार्यक्रम के तहत 9 विकास कार्यों के लिए 31 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग ने बताया कि आंगनबाड़ी की चारदीवारी निर्माण वार्ड नम्बर 3 शिखरानी के लिए 5 लाख रूपए, सार्वजनिक श्मशान घाट सुधार कार्य व गेट निर्माण के लिए 3 लाख रूपए, माध्यमिक विद्यालय लाम्बा में स्कूल खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण के लिए 3 लाख, राजपूत श्मशान घाट में विश्रान्ति गृह निर्माण के लिए 3 लाख, आंगनबाड़ी की चारदीवारी निर्माण सालरमाला के लिए 3 लाख, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालाहेडी की चारदीवारी को उंचा करने के लिए 3 लाख, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी निर्माण कार्य के लिए 3 लाख, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भरकाला स्कूल की चारदीवारी अपूर्ण को पूर्ण करने के लिए 5 लाख तथा श्मशान घाट में चारदीवारी निर्माण के लिए 3 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

बोर्ड चैयरमेन को पद से हटाने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से इंडियन मेडिसिन बोर्ड, राजस्थान के चेयरमैन को पद से हटाने पर आयुर्वेद सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग और इंडियन मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश वैद्य केदारनाथ शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता हर्षवर्द्धन नंदवाना ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता को राजस्थान इंडियन मेडिसिन एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर 5 जुलाई, 2018 को पांच साल के लिए इंडियन मेडिसिन बोर्ड, राजस्थान का चेयरमैन बनाया गया था। इसकी अवधि जुलाई 2023 में पूरी होने वाली थी, लेकिन राज्य सरकार ने गत 28 दिसंबर को याचिकाकर्ता को पद से हटा दिया। याचिका में कहा गया की याचिकाकर्ता वैधानिक पद पर कार्यरत था और राजस्थान इंडियन मेडिसिन एक्ट की धारा 15 के तहत बोर्ड चेयरमैन को पांच साल की अवधि से पहले नहीं हटाया जा सकता। याचिका में आरोप लगाया गया है की नई सरकार के गठन के तुरंत बाद राजनीतिक दुर्भावना से याचिकाकर्ता को पद से हटाया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अब जैव विविधता समितियों के गठन के लिए 15 दिन का समय दिया

जयपुर। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत स्तर पर जैव विविधता समितियों के गठन में देरी पर पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को फटकार लगाते हुए अब गठन के लिए 15 दिन का समय और दिया है। विभाग के शासन सचिव एस.एस. सोहता ने सभी जिला परिषदों को जैव विविधता प्रबंध समितियों के गठन के संबंध में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 की पालना में सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर एक जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन किया जाना था और साधारण सभा की बैठकों में प्रस्ताव पारित कराकर पालना रिपोर्ट पंचायती राज विभाग मुख्यालय भिजवानी थी। इससे पहले इस संबंध में पांच अक्टूबर को आदेश जारी किए थे, मगर चुनाव आचार संहिता लगने के कारण आदेशों की पालना नहीं होने के कारण प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए थे। अब जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समितियों के गठन के प्रस्ताव पारित करवाते हुए अगले 15 दिनों में पूर्ण प्रक्रिया के बारे में पंचायतीराज विभाग को जानकारी भिजवाई जाए।

दुष्कर्म पीडिता के सुरक्षित गर्भपात की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सामुहिक दुष्कर्म की शिकार 26 सप्ताह की गर्भवती महिला के सुरक्षित गर्भपात की जांच के लिए भरतपुर सीएमएचओ को दो महिला चिकित्सकों की मेडिकल टीम गठित करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की एकलपीठ ने यह आदेश दुष्कर्म पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि भरतपुर निवासी 24 वर्षीय विवाहिता का छह माह पहले कुछ लोगों ने सामुहिक दुष्कर्म किया था। इससे वह गर्भवती हो गई। याचिकाकर्ता दुष्कर्म से होने वाली संतान को नहीं अपनाना चाहती। इसके अलावा गर्भपात कराने की स्थिति में चिकित्सक उसे जान का खतरा बता रहे हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को गर्भपात कराने की अनुमति दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच के आदेश दिए हैं।

जेएलएफ में उठेगा जीन-रीडिंग मॉलिक्यूल के रहस्यों से पर्दा

जयपुर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन 24 से 28 जनवरी तक डिग्गी पैलेस आयोजित किया जाएगा। इस संस्करण में क्लासिक्स, युद्ध, जासूसी, खुफिया, राजनीति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, लैंगिक मसले, प्रबंधन उद्यमशीलता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही फिक्शन, पटकथा, पौराणिक कथाओं, अपराध, इतिहास, सिनेमा, कला, एक्टिविज्म और प्रवासन के मनोवैज्ञानिक परिणाम जैसे विस्तृत विषयों को शामिल किया गया है। इस दौरान बेन ओक्री लेखन के बारे में साथी उपन्यासकार राणा दास गुप्ता के साथ बात करेंगे। वहीं खगोलविद तथा येल की प्रोफेसर प्रियम्वदा नटराजन, रॉयल सोसायटी के अध्यक्ष एवं जीन मशीनः द रेस टू डेसिफर द सीक्रेट ऑफ द रिबोसम के लेखक और नोबल पुरस्कार विजेता वैंकी रामाकृष्णन से परिचय कराएंगी, जो जीन मशीन एंड द साइंस ऑफ कल्चर सत्र में अपने काम के बारे में बताएंगे और मानव की सबसे बड़े पहेली जीन-रीडिंग मॉलिक्यूल के रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। 'बीफोर एंड ऑफ्टर पाई' सत्र में मैन बुकर पुरस्कार विजेता यान मार्टेल उपन्यासकार जैरी पिंटो के साथ अपने लेखन के विषय से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त 'इंडिया डिसाइड्सः द ग्रेट मार्च टु डेमोक्रेसी' में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों में स्वतंत्र एवं निश्पक्ष चुनाव कराने और भारत के व्यापक मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक लाने की वास्तविक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।

पशुआहार संयंत्र का घूसखोर मैनेजर चढ़ा एसीबी के हत्थे

ठेकेदार से 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते धरा गया

अजमेर 08 जनवरी । अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए पशु आहार संयंत्र मैनेजर को 40 हजार रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित मैनेजर राजेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा यह रिश्वत लेबर ठेकेदार से बिल पास करने के बदले में मांगी गई थी। लेबर कांट्रेक्टर भंवर राजवीर सिंह द्वारा अजमेर एसीबी चौकी को विगत 2 जनवरी को शिकायत दी गई थी।

संयंत्र के ठेकेदार भंवर राजवीर सिंह ने शिकायत दी थी कि मैनेजर राजेन्द्र सिंह राठौड़ बिल पास करने के प्रतिमाह 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत का सत्यापन करवाया गयाए जांच में सही पाए जाने पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गत दिनों मैनेजर ने करीब 17 लाख रुपए के दो बिल पास भी किएए लेकिन दोनों बिलों की राशि स्वीकृत करने के लिए 40 हजार रुपए की मांग की। एसीबी की योजना के अनुरूप 8 जनवरी को जब शिकायतकर्ता राजवीर सिंह 40 हजार रुपए की रिश्वत दे रहा था। इसी दरम्यान टीम ने पकड़ लिया। यह राशि संयंत्र में ही ली जा रही थी।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अपनी फर्म हिडन आई सिक्युरिटी सर्विसेज के माध्यम से संयंत्र में कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध करवाता है। गरीब श्रमिकों के वेतन के बिल पास करने के लिए ही प्रतिमाह 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। रंगे हाथों पकड़ने के बाद राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कैटल फीड प्लांट के मैनेजर राजेंद्र सिंह के चंद्रवरदाई नगर स्थित निजी आवास के साथ ही अन्य ठिकानों की भी तलाशी ली है।पूर्व मैनेजर सुरेन्द्र शर्मा को भी पकड़ा था। करीब सात आठ वर्ष पहले इसी संयंत्र के मैनेजर सुरेन्द्र शर्मा को भी एसीबी ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था तब शर्मा के ठिकानों से कई करोड़ रुपए की राशि और जायदाद मिली थी। इस मामले में शर्मा को न्यायालय से सजा भी हुई। पूर्व मैनेजर की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी एसीबी गिरफ्तार मैनेजर राठौड़ की सम्पत्तियों का पता लगाने में लगी हुई है। उल्लेखनीय है कि संयंत्र में पशुओं के लिए आहार तैयार किया जाता है जिसे सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों को वितरित किया जाता है। यही वजह है कि संयंत्र में करोड़ों रुपए की सामग्री की सप्लाई होती है। यह सप्लाई भी ठेकेदार ही करते हैं।

अजमेर में कांग्रेस संगठन को बनाया जाएगा और मजबूत-प्रमोदजैन भाया

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली के लिए कांग्रेसियों को न्यौता

अजमेर। अजमेर के प्रभारी एवं खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि अजमेर में कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजमेर ने विधानसभा चुनाव में जो परिणाम दिए हैं उसका आकलन किया गया है। जो कमियां रही हैं उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस जो कहती है वह करती है उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है यह काम भाजपा का है जो सिर्फ कमियां ही निकालती है।

प्रमोद जैन भाया रविवार को अजमेर में मीडिया से बात कर रहे थे। प्रमोद जैन ने कहा कि वे जयपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान रैली में अजमेर से अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस जन को जयपुर ले जाने के विषय में कार्ययोजना बनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों एवं अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। विधानसभा क्षेत्रवार कांग्रेस जन को जयपुर किसान रैली में शामिल होने के लिए तैयारी की जा रही है। भाया ने कहा कि भाजपा ने किसानों को 50 हजार रुपया कर्जमाफी का वादा भी पूरा नहीं किया। राजस्थान ने कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार का गठन किया है इसी लिए राजस्थान में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को ही सरकारी दस्तावेज बनाकर उसपर काम शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने जो चुनाव में घोषणा की थी उसके तहत उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर राजस्थान की नवगठित अशोक गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का ऐतिहासिक निर्णय किया। उसके लिए राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कर रही है उसका सीधा लाभ आम गरीब जनता व किसानों को मिलेगा। भाजपा तो सिर्फकमी निकालने का काम करती हैं। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया इस दौरान शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली । शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन और देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ए पूर्व मेयर कमल बाकोलिया, पूर्व विधायक रामनारायण, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर प्रदेश महासचिव ललित भाटी, हेमंत भाटी, प्रतापसिंह यादव सहित अनेक कांग्रेस जन मंच पर मौजूद रहे।

पन्द्रह वर्षों से नियमितिकरण का कर रहे हैं इन्तजार एड्स परियोजना के संविदा कार्मिक

संविदा कार्मिकों को है हाईरिस्क पर नहीं हो रही नौकरी फिक्स

अजमेर 8 जनवरी। राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी जयपुर के अधीनस्थ पिछले लगभग 15 वर्षों से अल्प वेतन पर कार्य कर रहे एड्स परियोजना के संविदा कार्मिकों को अपने जीवन की हाईरिस्क तो है पर उनकी नौकरी फिक्स नहीं है। कांग्रेस राज आते ही इन कार्मिकों को एक बार फिर उम्मीद बनी है कि अशोक गहलोत सरकार उनकी तरह संवेदनाभरी दृष्टि जरूर डालेगी। ए.आर.टी. सेन्टर अजमेर के डाटा मैनेजर यतीश अग्रवाल के अनुसार राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के अधीन पूरे राज्य में लगभग 450 संविदा कार्मिक विभिन्न पदों जैसे डाटा मैनेजर, काउन्सलर, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन, स्टाफ नर्स, सुपरवाईजर, सी.सी.सी. इत्यादि पदों पर कार्य कर रहे हैं। अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव के 11 मार्च 2013 को जारी आदेश क्रमांक 270/2013 के तहत एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के कार्मिकों को राज्य सरकार के अधीन ही मानते हुये आवेदित पद के समान कार्य के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दे दिये गये थे। राजस्थान के सभी संविदा कर्मचारियों ने आवेदन शुल्क जमा करवा दिया था परन्तु वर्ष 2014 में सरकार बदलते ही भर्ती को रद्द कर दिया गया था।

कार्मिकों के अनुसार कांग्रेस सरकार ने संविदाकर्मियों के स्थायीकरण को लेकर घोषणा पत्र के श्रम एवं रोजगार के बिन्दु संख्या 3 में संविदा कर्मियों को बोनस अंक के आधार पर घोषणा की थी ऐसे में समस्त कार्मिकों ने सम्पूर्ण राजस्थान में वर्तमान सरकार के पक्ष में मतपूर्वक समर्थन किया था। सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में कार्यरत नर्सिंग स्टॉफ एवं लैब टैक्नीशियन को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देते हुये सीधी भर्ती के माध्यम से पांच वर्ष पूर्व नियमित कर दिया गया परन्तु उन्हीं के साथ कार्यरत डाटा मैनेजर, काउन्सलर, फार्मासिस्ट एवं केयर कॉर्डिनेटर को छोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार राजस्थान में लगभग 62 हजार एच.आई.वी. मरीजों के साथ कार्य करते हुये संविदा कार्मिकों को हमेशा संक्रमण का खतरा बना रहता है एवं इन मरीजों की जांच हेतु ब्लड सेम्पल लेने वाले कार्मिक भी हाईरिस्क पर रहते हैं। प्रतिवर्ष कई संविदाकर्मी इंफेक्शन की वजह से बीमार भी हो जाते हैं बावजूद इसके सरकार द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है। हाल ही में सरकार के नवगठन के साथ ही चिकित्सा मंत्री बनाए गए डॉ. रघु शर्मा को संविदा कार्मिकों ने अपनी पीड़ा से अवगत कराते हुए उनसे नौकरी फिक्स करने की मांग की है। कार्मिकों ने बताया कि पिछले 10.12 वर्षों में सभी कार्मिकों ने नियमितिकरण एवं समान कार्य समान वेतन को लेकर भी कई बार मांगे उठाई हैं किन्तु सरकार द्वारा एड्स कार्मिकों के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये।

वार्षिक वेतन वृद्धि घटा दी-एएआरण्टी सेन्टर पर काउन्सलर के पद पर कार्यरत पुष्पा प्रजापति एवं सीमा कुमावत ने बताया कि जहां सरकार ने सभी नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सातवां वेतन आयोग की सौगात दी वहीं सभी एड्स कार्मिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दी गई।

किस्मत ने भी नहीं दिया साथक-ए.आर.टी. सेन्टर अजमेर के काउन्सलर मोण् सलीम खां ने बताया कि उनकी तो किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। वर्ष 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 1311 दिनांक 10 जुलाई 2013 द्वारा संविदा कार्मिकों हेतु बोनस अंक देते हुये सीधी भर्ती निकाली थी परन्तु कुछ समय बाद आचार संहिता लगने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई और वर्ष 2014 में भाजपा सरकार ने इस भर्ती को खारिज़ कर सभी संविदा कार्मिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

परामर्शदाता का नहीं कोई कैडर-ज.ला.ने. चिकित्सालय के ब्लड बैंक काउंसलर गंगासिंह ने बताया कि सरकार ने सभी संविदा कर्मियों हेतु कैडर बना रखा है परन्तु परामर्शदाता हेतु अभी तक कोई कैडर नहीं बनाया है जिससे परामर्शदाताओं को अनुभव आधारित बोनस अंक नहीं मिल पाते हैं।

एन ओ सी जारी की जा चुकी है-आई.सी.टी.सी. काउन्सलर रितेश सैमसन ने बताया कि नेशनल एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा वर्ष 2014 में देश के सभी राज्य सरकारों को संविदा एड्स कार्मिकों हेतु एन.ओ.सी.जारी कर दी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्य सरकार यदि एड्स कार्मिकों को अपने स्तर पर नियमित करती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति की ओर से निकाली गई रैली

केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाला गुबार

मजदूर संगठन हड़ताल में शामिल हुए और रैली निकाल कर केन्द्र सरकार के खिलाफआक्रोश जताया।

अजमेर 08जनवरी। केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी जनविरोधी, आर्थिक विरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय श्रम संगठनों व अखिल भारतीय फैडरेशन के राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के आव्हान पर मंगलवार को कई केन्द्रीय व राज्य के कर्मचारी व मजदूर संगठन हड़ताल में शामिल हुए और रैली निकाल कर केन्द्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया।

संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति की ओर से निकाली गई रैली, सभा व हड़ताल में बैंक कर्मी, एलआईसी, इंश्योरेंस, रेलवे कर्मचारी सहित कई कर्मचारी शामिल हुए,जिससे बैंकों सहित कई सरकारी विभागों का कामकाज भी प्रभावित हुआ।

मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 18 हजार मासिक, महंगाई पर रोक लगाने, उपभोक्ता वस्तुओं में वायदा व्यापार व सट्टे पर प्रतिबंध लगाने, सरकारी भर्ती करनेए रोजगार देने, श्रम कानून को सख्ती से लागू करने, श्रमिक विरोधी नीतियों में संशोधन करने, सामाजिक सुरक्षा लागू करने व न्यूनतम पेंशन पांच हजार रुपए करने, रेलवे, रक्षा. बीमा. बैंक. अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णय वापस लेने, निजीकरण बंद करने, किसानों का कर्ज माफ कर फसल का उचित दाम देने व नेशनल पेंशन स्कीम खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित कई मांगें उठाई। मांगों को लेकर अलवर गेट एलआईसी कार्यालय से रैली निकाली और सभा की गई। जिसमें संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष मोहन चैलानीए संयोजक सुनील कुमार पुट्टी, अरुण गुप्ता, रवि वर्मा, गिरिराज प्रसाद उपाध्याय, कांति कुमार शर्मा, उमेश उपाध्याय, बनवारी लाल जांगिड़, गणपत लाल गौरा, प्रदीप कृपलानी, संजीव खन्ना आदि शामिल हुए। इस रैली व सभा में दवा प्रतिनिधि, बीएसएनएल, रोडवेज, पोस्ट ऑफिस, एचएमटी, लघु उद्योग निर्माण मजदूर व राज्य के कई घटक शामिल हुए।

नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफइंश्योरेंस वर्कर नहीं हुए हड़ताल में शामिल-श्रमिक संगठनों की दो दिवसीय हड़ताल में नेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफइंश्योरेंस वर्कर शामिल नहीं हुए और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने कामकाज किया।

नार्दन जोन के जनरल सेक्रेटरी कानसिंह राठौड़ ने बताया कि कुछेक संगठन हैं जो राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं। इस हड़ताल में अजमेर, कोटा, ब्यावर व शाहपुरा आदि स्थानों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल नहीं हुए।

भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा पर हुआ चिंतन

रुक्टाराष्ट्रीय का 57वां वार्षिक प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न

अजमेर।राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 57वां दो दिवसीय वार्षिक प्रदेश अधिवेशन 6 व 7 जनवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में सम्पन्न हुआ।

अधिवेशन के दूसरे दिन प्रातः 9 बजे भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा आवश्यकता चुनौतियाँ एवं समाधान विषय पर एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉ ओम प्रकाश पारीकए डॉ रेखा यादव, डॉ कश्मीर भट्ट, डॉ राजेश जोशी, डॉ सरोज कुमार, डॉ हरि सिंह, डॉ आदित्य गुप्ता, डॉ बबीता, डॉ अनिल गुप्ता,डॉ सरस्वती मित्तल आदि विषय विशेषज्ञों द्वारा शोधपत्र पढ़े गए तथा उन पर उपस्थित शिक्षकों द्वारा चर्चा की गई। संगोष्ठी में मुख्यवक्ता प्रो सुरेंद्र भटनागर रहे तथा अध्यक्षता प्रो भगीरथ सिंहए कुलपतिण् महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालयएबीकानेर ने की। डॉ सुरेंद्र सोनी ने संगोष्ठी का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि इस शैक्षिक संगोष्ठी का विषय सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षणए संवर्धन व विकास पर केंद्रित रहा।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर ने अपने उदबोधन में महासंघ की कार्य संस्कृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन के ध्येय वाक्य विद्यार्थी हित में शिक्षाए शिक्षा के हित में शिक्षकए शिक्षक हित में समाज को बताते हुए कहा कि महासंघ सिर्फ अपनी मांगें मनवाने के लिए नहीं वरन शिक्षाए शिक्षक और समाज के हित में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान को लेकर सतत प्रयत्नशील रहता है। यह वर्ष पर्यंत शिक्षकों में सनातन परम्परानुसार कर्तव्य बोध दिवस वर्ष संवत्सर गुरु वंदन शिक्षा के विभिन्न आयामों तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन करवाता है।

रुक्टा राष्ट्रीय के महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने अधिवेशन आयोजन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रो बी पी सारस्वत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत बनाने के सूत्र दिए कि निजी जीवन में सदैव सुचिता रहेए व्यवहार कुशल बनें और ध्येय निष्ठा बनी रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष एवं राजस्थान विश्वविद्यालयए जयपुर के पूर्व कुलपति जेण् पीण् सिंघल ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। अंत में आयोजन सचिव डॉ सुशील बिस्सू ने आभार व्यक्त किया।

नई कार्यकारिणी गठित-अधिवेशन के अंतिम सत्र के दौरान ही अगले दो वर्ष के लिए रुक्टा ;राष्ट्रीयद्ध की नवीन कार्यकारिणी की भी घोषणा की गयीए जिसमें अध्यक्ष डॉ दिग्विजयसिंहए महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता और संगठन मंत्री डॉ दीपक शर्मा सहित केंद्रीय कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया।कार्यक्रम का समापन सामूहिक वन्देमातरम और कल्याण मंत्र से हुआ। उल्लेखनीय है कि यह अधिवेशन पूर्णतया प्लास्टिक फ्री रखा गया। इस अधिवेशन में देशभर से अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपतिएशिक्षाविद एवं राजस्थान प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से रुक्टा ;राष्ट्रीय से सम्बद्ध शिक्षकों ने भाग लिया।

स्कूल छात्रा के साथ गैंगरेप मेडिकल मुआयना हुआ

पुलिस ने शुरू की आरोपितों की तलाश

अजमेर 08जनवरी। स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग दलित छात्रा को बेहोश कर अपहरण करने और उसके साथ छह युवकों द्वारा बारी बारी से बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

पुलिस ने मामला सामने आने के बाद पीड़ित दलित छात्रा का कल शाम को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल से बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना कराने के बाद आरोपित छह बदमाशों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। गैंग रेप का ताजा मामला क्रिश्चियन गंज पुलिस थाना क्षेत्र में गत 6 जनवरी को हुआ हैए जिसकी शिकायत पीडित किशोरी के पिता ने कल शाम को क्रिश्चियन गंज थाने पर दर्ज कराई है तथा मामले की जांच अजमेर उत्तर पुलिस उपअधीक्षक जिनेन्द्र जैन कर रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक पीड़ित दलित किशोरी स्कूली छात्रा हैए उसने अपने बयानों में बताया कि 6 जनवरी की शाम को माकड़वाली निवासी राजू गुर्जर, मनीष हरिजन, राहुल पंकज तथा आकाश ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसकी नाक पर जबरन रुमाल रख दियाए जिसके बाद उसके साथ क्या हुआए उसे पता नहीं तथा जब उसे होश आया तो उसने अपने को सुनसान जगह पाया।

स्वत्वाधिकारी व प्रकाशक नरेश राघानी के लिए राजेन्द्र वर्मा द्वारा अरावली प्रिंटिंग प्रेस 60 झलकारी नगर, अलवर गेट, अजमेर से मुद्रित व कार्यालय हॉराइजन हिन्द, बी-36बी, अहिंसा मार्ग, बी-ब्लॉक, पंचशील, अजमेर से प्रकाशित। सम्पादक- नरेश राघानी